

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

समक्ष जसजीत सिंह बेदी जे.

वीरेंद्र कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2018 का सीआरएम-ए नंबर 1313-एमए (ओ एंड एम)

01 दिसंबर 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 378-भारतीय दंड संहिता, 1860-उपधारा 306,107-विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील - आरोप है कि मृतक परेशान था क्योंकि उसने आरोपी संपत्ति विक्रेताओं को भूखंड खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जिसे उन्होंने न तो खरीदा और न ही पैसे वापस किए-घटना के दिन, मृतक ने परिवार को बताया कि वह पैसे लेने जा रहा था-इसके बाद उसने नहर में कूदकर अपनी जान ले ली -यह सवाल उठाया गया है कि क्या अभियुक्त की कथित कार्रवाई आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसाने का अपराध है -अभिनिर्धारित किया गया कि उपधारा 107 और 306 की पृष्ठभूमि में मामले की जांच करने पर कोई अपराध नहीं बनता है -अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य न तो पुरुष अधिकार को साबित करता है, न ही किसी प्रत्यक्ष या सक्रिय कार्य को साबित करता है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली-अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को इसके अंकित मूल्य पर सही मानते हुए, आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं किया जाएगा -जब विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है, तो अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है-विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है और अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित है-विवादित निर्णय विकृत नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है -खारिज कर दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि किसी अपीलीय न्यायालय को उन साक्ष्यों की समीक्षा करने, उनका पुनर्मूल्यांकन करने और उन पर पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है जिन पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया है, तथापि यह समान रूप से सत्य है कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है, पहला अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषता की धारणा के कारण और दूसरा इस तथ्य के कारण कि सक्षम न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है और इसलिए, यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव थे, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त करने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की तुलना में भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। हालांकि, जहां निर्णय के खिलाफ अपील की गई है वह पूरी तरह से विकृत है और निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं या

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अस्वीकार्य सामग्री, तब अपीलीय न्यायालय उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें दरकिनार करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा (पैरा 16)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि इसके ऊपर की विस्तृत चर्चा और माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर एक उचित दृष्टिकोण है, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 17)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशित मलिक।

नीरज पोसवाल, सहायक ए.जी., हरियाणा।

जसजीत सिंह बेदी, जे (मौखिक)

(1) आवेदक/अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश दिनांक 19.12.2017 के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया है, जिसके तहत अभियुक्त प्रत्यर्थी नंबर. 2/- जगदीश डिंगरा @पप्पू को आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 17.08.2015 को टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि देवेंद्र उर्फ रिकू की मौत गांव उधारसी के पास भाखड़ा नहर में डूबने से हुई है। जब एस. आई. चनान राम, ए. एस. आई. राज कुमार, ए. एस. आई. नरेश कुमार, एच. सी. मनोज कुमार के साथ भाखड़ा नहर गांव उधारसी की ओर बढ़ रहे थे, तो शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार और डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस स्टेशन, शाहाबाद के गेट के सामने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रोशन लाल की आटा मिल के पास घर संख्या 227/4, मोहल्ला खटरवाड़ा का निवासी था और वे दो भाई थे। वह देवेंद्र उर्फ रिकू से बड़ा था, जो शादीशुदा था और कपड़े का व्यवसाय करता था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। 4-5 महीने पहले देवेंद्र उर्फ रिकू ने 6,00,000 रुपये प्रॉपर्टी डीलर जगदीश उर्फ पप्पू ढींगरा बेटे देसराज निवासी तांगे वाली गली माजरी मोहल्ला, शाहाबाद मार्कंडा को एक प्लॉट खरीदने के लिए दिए थे और 8,00,000 रुपये की राशि प्रॉपर्टी डीलर गुरमीत सिंह बेटे करम सिंह निवासी गांव चारुनी को दी थी। पैसा उनकी फर्म से दिया गया था। भुगतान के बावजूद, दोनों अभियुक्तों ने अपने भाई के लिए कोई भूखंड नहीं खरीदा और न ही पैसे वापस किए। उसका भाई परेशान रहता था और अपने पैसे खोने के डर से तनाव में रहता था। 17.8.2015 को, लगभग 6.15 a.m. पर, उनके भाई ने स्विफ्ट कार में घर छोड़ दिया, पंजीकरण संख्या एच.आर -

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

78-9191. जाते समय उसने उनसे कहा कि वह पैसे इकट्ठा करने जा रहा है। लगभग पूर्वाह्न 8.15 पर, उन्हें (शिकायतकर्ता) को टेलीफोन पर सूचना मिली कि उनकी कार (मृतक की) गांव डल्ला माजरा में नहर के पास खड़ी थी और कार के पास एक चाबी के साथ चप्पल पड़ी थी। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि देवेंद्र उर्फ रिकू ने नहर में डूबकर अपनी जान दे दी है। उसके भाई ने आरोपी जगदीश उर्फ पप्पु और गुरजीत सिंह के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। बाद में, उरसी गांव के पास नहर से शव बरामद किया गया। वे शव को सिविल अस्पताल, कुरुक्षेत्र ले गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

(3) एफआईआर के पंजीकरण के अनुसार, धारा 173 सी.आर.पी.सी के तहत एक जांच और रिपोर्ट की गई थी। प्रस्तुत किया गया था।

(4) आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, उसे अदालत द्वारा दिनांक 19.08.2016 के आदेश के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और मुकदमे का दावा किया था।

(5) अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 वीरेंद्र कुमार, शिकायतकर्ता की जांच की, जिसने अपनी शिकायत प्रदर्शनी पी 1 की तर्ज पर गवाही दी, जिसे उसने साबित किया। उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई का शव भाखड़ा नहर से उदारसी के पास मिला था और पुलिस ने धारा 175 सी.आर.पी.सी के तहत सुशील कुमार, उनके दोस्त और उनके मामा ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए। उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने शव की पहचान की, जिसे उन्हें रसीद प्रदर्शनी पी2 के माध्यम से दिया गया। पुलिस ने एक प्लास्टिक की बोतल में नहर से पानी लिया जिसे रिकवरी मेमो के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। प्रदर्शनी पी3 नंबर एच आर - 78-9191 नंबर वाली स्विफ्ट कार और एक जोड़ी चप्पल को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। प्रदर्शनी पी 4 कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रदर्शनी पी 5 थी। कार की तलाशी ली गई और ज्ञापन प्रदर्शनी पी6 तैयार किया गया। वे कार को सुपरदारी वीडियो मेमो पर ले गए प्रदर्शनी पी 7 उसके मामा ओम प्रकाश का बयान प्रदर्शनी पी 8 पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने 17.08.2015 को प्रदर्शनी पी 2, प्रदर्शनी पी 4, प्रदर्शनी पी 6, प्रदर्शनी पी 7 और प्रदर्शनी पी 8, चैपल प्रदर्शनी पी 9 और प्रदर्शनी पी 10 पर अपने मामा ओम प्रकाश के हस्ताक्षरों की पहचान की और कहा कि वे कार के पास पड़े हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि उसके भाई देवेंद्र उर्फ रिकू ने आरोपी जगदीश ढींगरा उर्फ पप्पु और गुरजीत सिंह द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। उनके भाई ने 9896327235 और 9254000034 मोबाइल फोन नंबरों का इस्तेमाल किया, जबकि उनके मोबाइल फोन नंबर 9416292759 और 9996139459 थे। उसका भाई अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के कारण अवसाद में था और वह उसे, अपनी पत्नी और माँ को उत्पीड़न के बारे में बताता था। मृतक देवेंद्र ने परिवार के सभी सदस्यों को सभी तथ्य बताए और

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

उन्हें कोई समाधान खोजने के लिए कहा।

पीडब्लू-2 प्रेम सिंह, कैनाल पटवारियों ने घटना स्थल, गांव डल्ला माजरा, नरवाना ब्रांच कैनाल के स्केल्ड साइट प्लान प्रदर्शनी पी 11 को साबित किया, जिसे उन्होंने एसआई चानन राम के सीमांकन पर 30.09.2015 को तैयार किया था।

पीडब्लू-3 ईएचसी राजेश कुमार ने बिना किसी देरी के इलाका मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र और पुलिस उपाधीक्षक, शाहाबाद को मामले की विशेष रिपोर्ट सौंपी।

पीडब्लू-4 प्यारे लाल, कैनाल पटवाड़ी एसआई चानन सिंह के सीमांकन पर 30.09.2015 को हलका ज्योतिसार ने स्केल्ड साइट प्लान प्रदर्शनी पी 12 तैयार किया।

पीडब्लू-5 एसआई अजमेर सिंह ने 17.08.2015 को वीरेंद्र कुमार की शिकायत प्रदर्शनी पी 1 पर प्राथमिकी प्रदर्शनी पी 13 दर्ज की। उन्होंने शिकायत पर प्रदर्शनी पी 14 का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने ई एच सी राजेश कुमार के माध्यम से उच्च अधिकारियों को विशेष रिपोर्ट भेजी।

पीडब्लू-6 सी. करमबीर ने बताया कि 18.08.2015 को आवेदन प्रदर्शनी पी 15 को प्रभारी पुलिस पोस्ट सिटी शाहाबाद द्वारा कॉल विवरण रिकॉर्ड और मोबाइल फोन नंबरों के पते लेने के लिए प्रभारी साइबर सेल, कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। मृतक देविंदर @रिंकू का 98963-27235 और 92540-00034, मृतक की मां राज रानी का मोबाइल फोन नंबर 85720-94272 और शिकायतकर्ता वीरेंद्र का मोबाइल फोन नंबर 99961-39459। उन्होंने ईमेल के माध्यम से संबंधित सेवा प्रदाताओं से कॉल विवरण रिकॉर्ड प्राप्त किया और प्रिंट-आउट प्रदर्शनी पी 16 को प्रदर्शनी पी 18 और धारकों प्रदर्शनी पी 19 के पते वाली सूची एसआई चानन राम जांच अधिकारी को सौंप दी, जिन्हें मेमो प्रदर्शनी पी 20 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। उनका बयान एस. आई. चानन राम ने दर्ज किया।

पीडब्लू-7 एचसी अजय ने विसरा का एक सीलबंद पार्सल, निदेशक, एफएसएल मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा और निदेशक, एफएसएल मधुबन के साथ डॉक्टर की नमूना मुहर 27.08.2015 को जमा की और एमएचसी करमबीर को रसीद दी। उन्होंने आगे बताया कि 01.09.2015 को, एमएचसी करमबीर ने उन्हें मृतक के रक्त वाली एक सीलबंद शीशी, निदेशक, एफएसएल मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा, डॉक्टर की नमूना मुहर और एक सीलबंद पानी की बोतल के साथ जांच अधिकारी की नमूना मुहर निदेशक, एफएसएल मधुबन के पास जमा करने के लिए सौंपी। उसने वही एफएसएल मधुबन में जमा किया और रसीद एमएचसी करमबीर को दे दी। इस अवधि के दौरान मामले की संपत्ति उनके पास रही, उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की।

पीडब्लू-8 डॉ. संजीव शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र ने अपना विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किया

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

प्रदर्शनी पी 21 दिलबाग राय के बेटे देवेंद्र कुमार के मृत शरीर पर पोस्टमॉर्टम परीक्षा के संबंध में, पोस्टमॉर्टम परीक्षा और पुलिस को सौंपी गई सामग्री के समय चोटों का उल्लेख किया गया। उन्होंने पी एम आर प्रदर्शनी पी 22 की प्रति साबित की और उस पर डॉ. गौरव चावला के हस्ताक्षरों की पहचान की। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्शनी पी 23 और प्रदर्शनी पी 24 को देखने के बाद, उन्होंने कहा कि देवेंद्र की मौत का कारण डूबना था, न कि कोई सामान्य जहर। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम के बाद विसरा वाला एक सीलबंद बॉक्स, निदेशक, एफएसएल, मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा, खून की एक सीलबंद शीशी और दो सैंपल सील सब इंस्पेक्टर चनन राम को सौंप दिए गए।

पीडब्लू-9 एचसी करमबीर ने बताया कि 17.08.2015 को एसआई चनन राम प्रभारी पुलिस चौकी हुडा, शाहाबाद ने अपने साथ एक सीलबंद बॉक्स, खून की एक सीलबंद शीशी, निदेशक एफएसएल मधुबन को संबोधित दो लिफाफे, डॉक्टरों की दो सैंपल सील, एक सीलबंद पानी की बोतल और जांच अधिकारी की एक सैंपल सील जमा की, जिसे उन्होंने रजिस्टर नंबर 19 में सीरियल नंबर 396/15 पर दर्ज किया। उन्होंने कहा कि 27.08.2015 को उन्होंने एफएसएल मधुबन में जमा करने के लिए ईएचसी अजय कुमार को एक सीलबंद बॉक्स, एक लिफाफा, एक नमूना मुहर सौंपी, जिन्होंने उसी दिन एफएसएल मधुबन में जमा किया और उसे रसीद दी। उन्होंने बताया कि 01.09.2015 को उन्होंने एफएसएल मधुबन में जमा करने के लिए ईएचसी अजय कुमार को रक्त की एक सीलबंद शीशी, एक लिफाफा, एक नमूना सील, एक पानी की बोतल और जांच अधिकारी की एक नमूना सील सौंपी। उसी दिन उन्होंने उसे एफएसएल मधुबन में जमा कर दिया और रसीद उन्हें सौंप दी। उसके पास रहने की अवधि के दौरान मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

पीडब्लू 10 डॉ. प्रिया चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, फॉरेंसिक प्रयोगशाला, मधुबन ने डायटम जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक, शाहाबाद के अनुरोध पर जीव विज्ञान प्रभाग, एफएसएल, मधुबन में कांस्टेबल अजय कुमार के माध्यम से 01.09.2015 को प्राप्त रक्त के नमूने की एक शीशी और पानी की एक बोतल वाले सीलबंद पार्सल पर डायटम जांच की। उन्होंने कहा कि रक्त के नमूने की एक शीशी और पानी के नमूने की एक बोतल वाले पार्सल में मुहरें बरकरार थीं और डायटम जांच प्रदर्शनी 1 रक्त के नमूने और प्रदर्शनी 2 पानी के नमूने में की गई थी जो समान प्रकार के पाए गए थे। उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्शनी पी 23 दी और जांच के बाद, पार्सल को सील 'पी सी एफ एस एल' के साथ फिर से सील कर दिया गया। उसने पानी की बोतल प्रदर्शनी पी 25 को अपनी मुहर 'पी सी एफ एस एल' के साथ साबित किया।

मृतक के पिता पीडब्लू-11 दिलबाग राय, मृतक के मामा पीडब्लू-12 ओम प्रकाश और मृतक की पत्नी पीडब्लू-13 किरण ने वीरेंद्र कुमार के बयान की पुष्टि की। पीडब्लू-1

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

मृतक देवेंद्र उर्फ रिकू द्वारा आरोपी जगदीश ढींगरा उर्फ पप्पु द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के संबंध में, जिसने न तो 6 लाख रुपये लौटाए और न ही उसके लिए कोई संपत्ति खरीदी।

पीडब्लू-14 इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने धारा 173 (2) सी.आर.पी.सी के तहत रिपोर्ट तैयार की। जांच पूरी होने पर 24.09.2015 को।

पीडब्लू-15 एसआई मामले की जांच करने वाले चानन राम ने कहा कि उन्हें 17.08.2015 को एक टेलीफोनिक संदेश मिला था कि देवेंद्र सिंह की गांव उदारसी के पास भाखड़ा नहर में डूबने से मौत हो गई थी। जब वे गाँव उदारसी जा रहे थे, शिकायतकर्ता वीरेंद्र ने उनसे पुलिस स्टेशन, शाहाबाद के पास मुलाकात की और एक आवेदन प्रदर्शनी पी 1 प्रस्तुत किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि जगदीश ढींगरा और गुरजीत सिंह द्वारा उनके भाई देवेंद्र को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने भाखड़ा नहर में आत्महत्या कर ली। उन्होंने पुलिस कार्यवाही प्रदर्शनी पी 29 का संचालन किया और एसआई नरेश कुमार को मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन, शाहाबाद भेजा। फिर वह एसआई राज कुमार और एचसी मनोज कुमार के साथ एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र पहुंचे और धारा 174 सी.आर.पी.सी के तहत प्रदर्शनी पी 30 जांच की कार्यवाही की। उन्होंने धारा 175 सी.आर.पी.सी के तहत सुशील कुमार और ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए। फिर, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नरेश कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। गाँव उदसी और बचगांव के पास भाखड़ा नहर और वीरेंद्र कुमार के कहने पर रफ साइट प्लान प्रदर्शनी पी 31 तैयार किया। उन्होंने नहर से पानी की बोतल प्रदर्शनी पी 32 ली, इसे सील 'एसआर' से सील कर दिया और इसे मेमो प्रदर्शनी पी 3 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया। फिर, वह ओम प्रकाश के साथ गाँव डल्ला माजरा गए। नंबर. एच आर - 78-9191 रजिस्ट्रेशन वाली स्विफ्ट कार वहां खड़ी थी। कार की चाबी और सैंडल्स प्रदर्शनी पी 10 की एक जोड़ी भी मिली। कार, चाबी और सैंडल को मेमो प्रदर्शनी पी 4 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि कार के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्शनी पी 5 थी। मेमो प्रदर्शनी पी 6 के माध्यम से कार की तलाशी ली गई। कार शिकायतकर्ता वीरेंद्र और ओम प्रकाश को मेमो प्रदर्शनी पी 7 के माध्यम से सुपरदारी पर दी गई थी। वसूली के स्थान की रफ साइट योजना प्रदर्शनी पी 33 तैयार की गई थी। एसआई राज कुमार ने उन्हें विसरा वाला एक सीलबंद पार्सल, एक रक्त की शीशी और एक अन्य सीलबंद जार के साथ नमूना सील और लिफाफा सौंपा, जिसे उन्होंने एमएचसी, पुलिस स्टेशन, शाहाबाद में जमा किया। 18.08.2015 को, आवेदन प्रदर्शनी पी 15 को प्रभारी साइबर सेल, एस.पी.में स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यालय, कुरुक्षेत्र उसमें उल्लिखित मोबाइल नंबरों का विवरण मांग रहा है। 22.08.2015 को, कॉल विवरण प्रदर्शनी पी 34 आईडी के साथ कांस्टेबल करमवीर द्वारा वितरित किए गए थे, जिन्हें ज्ञापन प्रदर्शनी पी 20 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया था। देवेंद्र का शव ओम प्रकाश और सुशील कुमार को ज्ञापन प्रदर्शनी पी 2 के माध्यम से सौंप दिया गया।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

(6) अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू डॉ. गौरव चावला, राज रानी, सुरजीत उर्फ सुशील कुमार और एसआई नरेश कुमार को अनावश्यक होने के कारण छोड़ दिया। इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया।

(7) आरोपी का बयान धारा 313 सी.आर.पी.सी के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने दोषारोपण करने वाले सबूतों को गलत बताते हुए इनकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

(8) रक्षा में, प्रदर्शनी डी 2, धारा 161 सी.आर.पी.सी के तहत दर्ज किरण के बयान की प्रति। उत्पादित किया गया था।

(9) विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि साक्ष्य और अभिकथनों को सत्य मानते हुए अभियुक्त की ओर से अपराध करने का कोई कारण सिद्ध नहीं हुआ और इस प्रकार उसे दिनांक 19.12.2017 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया जिससे वर्तमान अपील दायर की गई।

(10) आवेदक/अपीलार्थी के विद्वत वकील का तर्क है कि पीडब्लू-1/मृतक के भाई वीरेंद्र कुमार (शिकायतकर्ता) और पीडब्लू-11/दिलबाग राय (मृतक के पिता) ने अदालत में गवाही देते हुए पुलिस के समक्ष अपना पक्ष दोहराया और स्पष्ट रूप से कहा कि देवेंद्र @रिंकू (मृतक) ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि आरोपी भूखंड खरीदने के लिए उसके द्वारा दिए गए पैसे को वापस करने में विफल रहा था। वास्तव में, आरोपी व्यक्ति मृतक को धमकी दे रहे थे कि अगर उसने उसके पैसे वापस मांगे तो वे उसे मार देंगे और इसी कारण से आरोपी द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकी दिए जाने के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली। पीडब्लू-13/किरण (मृतक की विधवा) ने भी शिकायतकर्ता-पीडब्लू-1 के संस्करण के अनुरूप अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। इस प्रकार, वह तर्क देता है कि बरी किए जाने का निर्णय इसके विपरीत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है और बरी किए गए आरोपी को विचाराधीन अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

(11) मैंने आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

(12) आगे की कार्यवाही करने से पूर्व आई. पी. सी. की धारा 306 और आई. पी. सी. की धारा 107 के उपबंधों की जांच करना समीचीन होगा जिन्हें ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

आईपीसी की धारा 306 इस प्रकार है:-

306 आत्महत्या के लिए उकसाना - यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह उत्तरदायी भी होगा।

ठीक करने के लिए।

आई. पी. सी. की धारा 107 इस प्रकार है:-

किसी कार्य को करने के लिए उकसाना: एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, जो: पहले-किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है; या, दूसरा: उस कार्य को करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी भी साजिश में शामिल होता है, यदि कोई कार्य या अवैध चूक उस षड्यंत्र के अनुसरण में होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या तीसरा-जानबूझकर, किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा, उस कार्य को करने में सहायता करता है।

(13) उकसाने का अर्थ है किसी को ऐसा करने के लिए उकसाना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। यह आवश्यक नहीं है कि उकसाने के लिए व्यक्त शब्दों का उपयोग किया जाए। उकसाने से उकसाने का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो उकसाता है न कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर जो इस तरह से उकसाया गया है। इन सभी शब्दों के पीछे मूल भावना प्रेरित करना, उकसाना, सहायता करना, उकसाना या प्रोत्साहित करना, उन कार्यों या चूक में निहित है जो अभियुक्त ने शब्दों या इशारों से किए थे ताकि व्यक्ति को ऐसी मानसिक स्थिति में लाया जा सके कि ऐसी परिस्थितियों में, वह परिस्थितियों से इतना मजबूर होकर अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था।

(14) जब वर्तमान मामले की जांच आईपीसी की धारा 306 के साथ पठित आईपीसी की धारा 107 की पृष्ठभूमि में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि कोई भी अपराध नहीं बनाया गया है।

पीडब्लू 1/वीरेंद्र कुमार (मृतक के भाई) पीडब्लू-11/दिलबाग राय (मृतक के पिता) और पीडब्लू-13/किरण (मृतक की पत्नी) द्वारा लगाए गए आरोपों का समन और सार यह है कि मृतक-देवेंद्र @रिंकू ने बरी आरोपी-जगदीश ढींगरा को एक भूखंड खरीदने के लिए रु. 6 लाख की राशि दी थी और जब भी उसने आरोपी से अपने पैसे वापस या भूखंड की मांग की, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसे पैसे वापस नहीं किए गए। इस वजह से मृतक (देवेंद्र @रिंकू) अवसाद में था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। वास्तव में, इन गवाहों के बयानों में काफी सुधार हुआ है। धारा 161 सी.आर.पी.सी के तहत दर्ज प्रारंभिक बयानों में, हत्या की धमकी देने वाले आरोपी के संस्करण का उल्लेख नहीं मिलता है। यह संस्करण पहली बार आया है जब न्यायालय में उक्त गवाहों से पूछताछ की गई थी। इसलिए, बेहतर संस्करण पर विचार नहीं किया जा सकता है

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

अभियुक्त को दोषी ठहराएँ।

6 लाख रुपये की अग्रिम राशि के आरोपों को सही मानते हुए, यदि उक्त राशि मृतक को वापस नहीं की जा रही थी, तो उसके पास अदालत या जांच एजेंसियों से संपर्क करके कानून के अनुसार वसूली करने का विकल्प था। केवल इसलिए कि उक्त राशि वापस नहीं की जा रही थी या उक्त राशि से खरीदा जाने वाला प्रस्तावित भूखंड मृतक को नहीं दिया जा रहा था, यह उकसाने का मामला नहीं होगा।

यह कहने के बाद, यह इंगित किया जा सकता है कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि मृतक ने वास्तव में प्लॉट की खरीद के लिए आरोपी को 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। मृतक के परिवार के तीन सदस्यों-देवेन्द्र @रिंकू का अभियुक्त को पैसे देने के संबंध में बयान भी एक-दूसरे के विपरीत चल रहा है। पीडब्लू-1/वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि बैंक से पैसे निकालकर आरोपी को पैसे दिए गए थे और पीडब्लू-11/दिलबाग राय ने कहा है कि उसके बेटे ने अपनी मां से पैसे लेकर आरोपी को 6 लाख रुपये दिए हैं।

चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत कॉल विवरण रिकॉर्ड के साथ कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी और मृतक के बीच कॉल का आदान-प्रदान हुआ था और इस खाते पर भी आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के पूरे बयान को सही मानते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति को एक कार्य करने के लिए दूसरे को उकसाने के लिए कहा जाता है, जब वह सक्रिय रूप से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम या भाषा से कार्य करने का सुझाव देता है या प्रेरित करता है, चाहे वह व्यक्ति अनुरोध या संकेत, आक्षेप या प्रोत्साहन का रूप ले। एक व्यक्ति किसी कार्य के करने से पहले या उसके समय किए गए किसी कार्य में सहायता करके सहायता करता है, वह वास्तव में इसे करने में सुविधा प्रदान करने का इरादा रखता है और करता है। इरादा किसी अपराध में सहायता करने या अपराध करने में सहायता करने का होना चाहिए। इस मामले में, धारा 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट में कोई सीधा आरोप नहीं है। कि अभियुक्त ने कभी उकसाया, संलग्न किया, जानबूझकर किया या इस तरह की साजिश रची कि मृतक को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सबूत में पीडब्लू-13 किरण का बयान कि आरोपी ने मृतक को जाने और आत्महत्या करने के लिए कहा था, एक अलंकृत विचार के बाद का संस्करण है और यहां तक कि आरोपी पर दोष लगाने के लिए अपर्याप्त है। संजू @संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में

प्रदेश', जहां अभियुक्त ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और मृतक को 'जाने और मरने' के लिए कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उकसावे की बात नहीं की गई थी और झगड़े में या पल भर में बोले गए शब्दों को किसी भी पुरुष कारण के साथ नहीं लिया जा सकता है। स्वामी प्रहलाद बनाम स्टेट ऑफ़ एम. पी और अन्य 2, आरोपी पर आईपीसी की धारा 306 के तहत इस आधार पर अपराध का आरोप लगाया गया था कि झगड़े के दौरान उसने मृतक को 'जाने और मरने' के लिए कहा था। अदालत का विचार था कि आरोपी द्वारा मृतक को 'जाने और मरने' के लिए कहे गए शब्द प्रथम दृष्टया मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे।

इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, पीडब्लू-1/शिकायतकर्ता-विरेंद्र कुमार, पीडब्लू-11 दिलबाग राय और पीडब्लू-13 किरण के बयानों का उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने अपने निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य न तो आरोपी की ओर से अपराध करने के लिए किसी भी पुरुष कारण को साबित करता है और न ही किसी प्रत्यक्ष या सक्रिय कार्य को साबित करता है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली।

(15) जहां तक दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में कानूनी स्थिति और न्यायालय द्वारा आहूत हस्तक्षेप की गुंजाइश का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एम.जी.के मामले में। अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, निम्नानुसार अभिनिर्धारित है:-

(16) धारा 423 (1) उसके समक्ष प्रस्तुत अपीलों के निपटारे में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को विहित करती है और खंड (क) और (ख) क्रमशः दोषसिद्धि के विरुद्ध दोषमुक्ति और अपीलों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति, जो दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित है, खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति जितनी व्यापक है, जो दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित है, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि आपराधिक अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां समान रूप से व्यापक हैं चाहे प्रश्नगत अपील दोषमुक्ति के विरुद्ध हो या दोषसिद्धि के विरुद्ध। यह सवाल का एक पहलू है। प्रश्न का दूसरा पहलू उस दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिसे उच्च न्यायालय बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपीलों से निपटने में अपनाता है। इस तरह की अपीलों से निपटने में, उच्च न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को ध्यान में रखता है और हार नहीं सकता है

¹ 2002 (2) आर सी आर (सी आर एल) 687 (एस सी)

² 1995 एस सी सी (सीआरआई) 943

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अनुमान विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित बरी किए जाने के आदेश से मजबूत होता है और इसलिए, यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति एक उचित संदेह के लाभ का हकदार है, उच्च न्यायालय के दिमाग में हमेशा मौजूद रहेगा जब वह मामले के गुणागुण से संबंधित है। एक अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय आम तौर पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा होता है, विशेष रूप से जब उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित होता है क्योंकि विचारण न्यायालय को उन गवाहों के आचरण को देखने का लाभ होता है जिन्होंने साक्ष्य दिया है। इस प्रकार, यद्यपि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय की शक्तियां उतनी ही व्यापक हैं जितनी कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर विचार करने में उसके पास हैं, अपीलों के पूर्व वर्ग के साथ व्यवहार करते हुए, इसका दृष्टिकोण निर्दोषता के अनुमान से बहने वाले ओवरराइडिंग विचार द्वारा नियंत्रित होता है। कभी-कभी, शक्ति के विस्तार पर जोर दिया जाता है, जबकि अन्य अवसरों पर, बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, और समय-समय पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों या वाक्यांशों में जोर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक कानूनी स्थिति यह है कि बरी किए जाने के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण चाहे कितना भी चौकस और सतर्क क्यों न हो, वह निस्संदेह अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार है। इस स्थिति को शीओ स्वरूप बनाम द, किंग एम्परर, (1934) एल.आर में प्रिवी काउंसिल द्वारा स्पष्ट किया गया है। 61 आई.ए. 398: ए आई आर 1934 पीसी 227 और नूर मोहम्मद बनाम सम्राट एआईआर 1945 पीसी 151

(17) हालांकि, इस न्यायालय के पहले के कुछ निर्णयों में, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपीलों से निपटने में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए, यह देखा गया कि निर्दोषता की धारणा को बरी करने के आदेश से मजबूत किया जाता है और इसलिए, "निचली अदालत के निष्कर्ष जिन्हें गवाहों को देखने और उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ था, उन्हें केवल बहुत ही ठोस और सम्मोहक कारणों से उलट दिया जा सकता है": वीडियो सूरजपाल सिंह बनाम राज्य 1952-3 एस सी आर 193 पी.201 पर ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 52 इसी प्रकार अजमेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1953 एस सी आर 418: एआईआर 1953 एससी 76 में यह पाया गया कि

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और सम्मोहक कारण" हों। कुछ अन्य निर्णयों में, यह कहा गया है कि बरी किए जाने के आदेश को केवल "अच्छे और पर्याप्त ठोस कारणों" या "मजबूत कारणों" के लिए वापस लिया जा सकता है। इन टिप्पणियों के प्रभाव की सराहना करते हुए, यह याद रखना चाहिए कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक कठोर या कठोर नियम निर्धारित करना नहीं था जो बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय को नियंत्रित करता हो। संहिता की धारा 423 (1) के खंड (क) में एक अतिरिक्त शर्त प्रस्तुत करने के लिए उनका इरादा नहीं था, और उन्हें इरादा रखने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उक्त टिप्पणियों का उद्देश्य केवल इस बात पर जोर देना है कि बरी किए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए क्योंकि जैसा कि लॉर्ड रसेल ने शीओ स्वरूप के मामले में कहा था, अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती है कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है। इसलिए, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण" अभिव्यक्ति द्वारा सुझाए गए परीक्षण को एक सूत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसे हर मामले में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह इस न्यायालय के हाल के निर्णयों का प्रभाव है, उदाहरण के लिए, संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715 और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 439 में; और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से उसमें दर्ज निष्कर्षों को विकृत के रूप में चिह्नित करना चाहिए। इसलिए, वर्तमान अपीलों में हमें जो प्रश्न पूछना है, वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन मामला उचित संदेह से परे साबित हुआ था, और यह कि निचली अदालत द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण गलत था। इस प्रश्न का उत्तर देते समय, हम, निस्संदेह, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा की गई शिकायत की सराहना करने के लिए साक्ष्य की मुख्य और व्यापक विशेषताओं पर विचार करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत हम आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होंगे, विशेष रूप से जहां उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित हैं।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

सी. एंटनी बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। के.जी राघवन नायर 3, के रूप में निम्नलिखित आयोजित:-

"6. मामलों की एक संख्या में यह अदालत ने माना है कि हालांकि अपीलीय अदालत सबूत है जिस पर दोषमुक्ति के आदेश की स्थापना की जाती है की समीक्षा करने के लिए पूरी शक्ति है, अभी भी इस तरह के एक अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के एक मामले में, अपीलीय अदालत, न केवल तथ्य के प्रश्न पर एक असर होने रिकॉर्ड पर हर मामले पर विचार करना चाहिए और दोषमुक्ति के अपने आदेश के समर्थन में नीचे अदालतों द्वारा दिए गए कारणों, यह निर्णय में अपने कारणों को व्यक्त करना चाहिए जिसके कारण यह माना जाता है कि दोषमुक्ति उचित नहीं है। उन मामलों में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय को गवाहों को साक्षी पेटी में देखने का लाभ प्राप्त था और निर्दोष होने की धारणा दोषमुक्ति के आदेश से कमजोर नहीं होती है, और ऐसे मामलों में यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए। भीम सिंह रूप सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (1974 (3) एस. सी. सी. 762) और धरमदेव सिंह और अन्य देखें। बनाम बिहार राज्य (1976 (1) एससीसी 610) [जोर दिया गया]

राजस्थान राज्य बनाम मोहन लाल 4 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

5. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को देखते हुए, हम पहले कानूनी स्थिति पर विचार करना और स्पष्ट करना उचित समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXIX (धारा 372-394) (जिसे इसके पश्चात् "वर्तमान संहिता" कहा गया है) अपीलों से संबंधित है। धारा 372 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, सिवाय संहिता द्वारा या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा दिए गए प्रावधानों के। धारा 373 में कुछ मामलों में अपील दायर करने का प्रावधान है। धारा 374 दोषसिद्धि से अपील की अनुमति देती है। धारा 375 उन मामलों में अपील करने से रोकती है जहां आरोपी अपना दोष स्वीकार करता है। इसी तरह, छोटे मामलों में कोई अपील विचारणीय नहीं है (धारा 376) धारा 377

³ 2002 (4) आर.सी.आर. (सी आर एल.) 750

⁴ 2009 (2) आर.सी.आर. (सी आर एल.) 812

सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा अपील की अनुमति देता है।

धारा 378 राज्य को बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त खंड सामग्री है और इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है:

378 है। बरी होने के मामले में अपील--(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर और उपधारा (3) और (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।

(2) यदि ऐसे मामले में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा या इस संहिता के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा अपराध की जांच की गई है, तो केन्द्रीय सरकार लोक अभियोजक को दोषमुक्ति के आदेश से उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का भी निर्देश दे सकती है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के अतिरिक्त विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि शिकायत पर स्थापित किसी मामले में दोषमुक्ति का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, इस निमित्त शिकायतकर्ता द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उपधारा (4) के तहत कोई भी आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से संगणित।

(6) यदि, किसी मामले में, उपधारा (4) के अधीन दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील उपधारा (1) के अधीन या (2) उपधारा के अधीन नहीं होगी।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

6. जबकि धारा 379-380 अपील के विशेष मामलों को शामिल करती है, अन्य धाराएं अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती हैं।

7. यह कहा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जिसे इसके बाद "पुरानी संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) में कमोबेश इसी तरह के प्रावधान पाए गए थे, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति और इस न्यायालय के समक्ष भी विचार के लिए आए थे। चूंकि वर्तमान अपील में, हमें बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में एक अपीलीय अदालत की शक्ति के दायरे और दायरे को तय करने के लिए कहा गया है, हमने खुद को केवल एक पहलू यानी तक सीमित कर दिया है। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील।

8. ऊपर उद्धृत वर्तमान संहिता की धारा 378 (बरी किए जाने के मामले में अपील) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका द्वारा बरी किए जाने के विरुद्ध अपीलों से निपटने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जब ऐसी अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय को व्यापक रूप से साक्ष्य की पुनः सराहना, समीक्षा और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिस सामग्री पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है और ऐसे साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति होती है। तथ्य और कानून दोनों के सवाल उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में निर्धारण के लिए खुले हैं।

9. हालाँकि, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि बरी होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा इसकी पुष्टि और पुष्टि की जाती है।

34. उपरोक्त निर्णयों से, चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 92:2007 (4) एस. सी. सी. 415) में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों को बाहर निकाला गया था: -

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1) एक अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिसके आधार पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि। बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने का इरादा नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) तथापि, अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्त किए जाने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके लिए निर्दोष होने का अनुमान उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

[जोर दिया गया]

लूनाराम बनाम भूपत सिंह और अन्य ⁵ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"6. अपीलीय अदालत पर कोई प्रतिबंध नहीं है

⁵ 2010 (5) आर.सी.आर. (सी आर एल.) 530

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

उस साक्ष्य की समीक्षा करना जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने की धारणा को बरी करने से और मजबूती मिलती है। आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह उन साक्ष्य की पुनः सराहना करे जहां अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या अभियुक्तों में से किसी ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। (भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ एम. पी, 2003 (3) एस सी सी 21 देखें) बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अदालत द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हों। यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और इस प्रक्रिया में अप्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को अनुचित रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक बड़ा कारण है। इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973 (2) एससीसी 793) रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996 (9) एससीसी 225) जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000 (4) एससीसी 484) राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य (2003 (11) एससीसी 519) पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह (2003 (11) एससीसी 271) पंजाब राज्य बनाम फोला सिंह (2003 (11) एससीसी 58) सुचंद पाल बनाम फनी पाल (2003 (11) एससीसी 527) और सचचे लाल तिवारी बनाम यू. पी. राज्य। (2004 (11) एससीसी 410)

[जोर दिया गया]

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागभूषण बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

5.2 योग्यता पर अपील पर विचार करने से पहले, पर कानून

⁶ 2021 (5) एस सी सी 222

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

धारा 378 सी.आर.पी.सी के दायरे और दायरे को बरी करने के खिलाफ अपील। और बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार किया जाना आवश्यक है।

बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189 के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 378 सी.आर.पी.सी के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था। 1973 ई. पैराग्राफ 12 से 19 में, इसे इस प्रकार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:-

12. इस न्यायालय ने बार-बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के निर्णय को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार संभव हों, हालांकि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक संभावित हो सकता है। बरी किए जाने के निर्णय पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या विचारण न्यायालय के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे। अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था। इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय हो सकता है। (बालक राम बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.) (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर बनाम बिहार राज्य (1990) 4 एस सी सी 17, शैलेन्द्र प्रताप बनाम यू. पी राज्य (2003) 1 एस सी सी 761, नरेंद्र सिंह बनाम एम. पी राज्य (2004) 10 एस सी सी 699, बुद्ध सिंह बनाम यू. पी.राज्य (2006) एस सी सी 731, स्टेट ऑफ यू. पी. राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. रामा बनाम रामी रेड्डी (2008) 5 एस सी सी 535, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस सी सी 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम ए. पी. (2009) 16 एस सी सी 98 और राम सिंह बनाम एच. पी. राज्य (2010) 2 एस सी सी 445)

13. शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 में, प्रिवी काउंसिल ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: (आई. ए. पी. 404)

"... उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों को उचित महत्व देना चाहिए और हमेशा विचार करना चाहिए जैसे (1) निचली अदालत की विश्वसनीयता के बारे में ट्रायल जज के विचार।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

गवाह; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, एक ऐसी धारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती है कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय न्यायालय की सुस्ती जिसे गवाहों को देखने का लाभ था।

14. कानून के उपरोक्त सिद्धांत लगातार इस अदालत द्वारा पालन किया गया है। (तुलसीराम कानू बनाम राज्य ए आईआर 1954 एस सी 1, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आईआर 1957 एस सी 216, एम.जी देखें। अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आईआर 1963 एस सी 200, खेडू मोहटन बनाम बिहार राज्य (1970) 2 एस सी सी 450, सांबशिवन बनाम केरल राज्य (1998) 5 एस सी सी 412, भगवान सिंह बनाम एम. पी राज्य (2002) 4 एस सी सी 85 और गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरन (2007) 3 एस सी सी 755)

15. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी स्थिति को दोहराया (एस. सी. सी. पी. 432, पैरा 42):-

(1) एक अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिसके आधार पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छा और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि। बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने का इरादा नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) तथापि, अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्त किए जाने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान है

आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके पास उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

16. घुरे लाल बनाम यू.पी.राज्य (2008) 10 एस सी सी 450 में, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि जिन मामलों में विचारण न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया है, उनसे निपटने में अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय का दोषमुक्त होना इस धारणा को बल देता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के आचरण को देखने का विशिष्ट लाभ था और वह गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

17. राजस्थान राज्य बनाम नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368 में, न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों की पुनः जांच की और यह निर्धारित किया कि: (एस सी सी पी 374, पैरा 20) - 20 तक। बरी किए जाने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि आरोपी की ओर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं।

18. यू.पी.राज्य में बनाम बत्र (2009) 4 एस. सी. सी. 271, इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियां दी हैं जिनमें न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायोचित होगा। परिस्थितियों में शामिल हैं: (एससीसी पृष्ठ 286, पैरा 28)

"(i) उच्च न्यायालय का निर्णय स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

(ii) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के विपरीत हैं;

(iii) साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय का गंभीर गर्भपात हो गया;

(iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

गलत कानून और मामले के रिकॉर्ड पर तथ्यों के आधार पर अनुचित;

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में बेहद अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी होने का आदेश दर्ज किया है।

धनपाल बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 401 में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और आगे यह कि निचली अदालत का बरी होना उसकी बेगुनाही की धारणा को मजबूत करता है। एक नियमित तरीके से हस्तक्षेप जहां अन्य दृष्टिकोण संभव है, से बचा जाना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

(जोर दिया गया)

5.2.2 जब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है, तो उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में निपटा गया है और उस पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार है: "20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या अपवर्जन करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं। निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के भार के खिलाफ" है, या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दुष्प्रभाव से पीड़ित है। (राजेंद्र कुमार किन्द्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1984) 4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम सी. सी. ई. 1994 सप्लीमेंट। (3) एस सी सी 665, गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस सी सी 501, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस सी सी 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम ए.पी राज्य (2009) 10 एससीसी 636)

(जोर दिया गया)

5.2.3 आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1999) 2 एस. सी. सी. 10 के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण करने के पश्चात्, यदि कोई विनिश्चय बिना किसी साक्ष्य या पूर्णतः अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर किया जाता है और कोई युक्तियुक्त व्यक्ति उस पर कार्य नहीं करेगा तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

5.3 विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एस. सी. सी. 436 के मामले में, इस न्यायालय को धारा 378 सी.आर.पी.सी, 1973 के दायरे और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर फिर से विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

"31. उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पृ. 233)"10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि वे सबूतों के उचित मूल्यांकन के बाद आए। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

31.1 संबाशिवन बनाम कराला राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412 में, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की पुनःप्रशंसा पर दोषी ठहराया।

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के प्रत्यावर्तन पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश विकृत था और दुर्बलता से ग्रस्त था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया: (एस सी सी पी. 416)".

8. हमने यह पता लगाने के लिए अपील के तहत दिए गए फैसले का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबुला दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्यवाही नहीं की है। सबसे पहले इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करना कि क्या साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए सभी तर्कों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन अपील के तहत फैसले को दरकिनार करने को उचित ठहराएगा? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण, जो किसी अपीलीय न्यायालय के निर्णय की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए। परन्तु यदि दूसरी ओर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि दोषमुक्ति के आदेश में अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं था; तो ऐसे मामले में

अपीलीय न्यायालय को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, केवल बरी होने के समर्थन में एक को खड़ा होना चाहिए। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

31.2. के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम कराला राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 309 वाले मामले में यह मत व्यक्त करने के पश्चात् कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वत वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह पाया गया था कि दोषमुक्ति के आदेश को अभिलिखित करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और कई पहलुओं पर विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करने में न्यायोचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से हकदार था। इस न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और कहा कि निचली अदालत द्वारा चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए प्रस्तुत किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3. एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य. ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया: (ए. आई. आर. पीपी. 809-10)

"5. अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का निर्णय बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य की केवल सराहना पर इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए था, जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि निचली अदालत का निर्णय विकृत था। हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत धारा 417 सी.आर.पी.सी. के तहत एक अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि अपील के तहत बरी होने का निर्णय विकृत था, वह उस आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता था।

यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि यह खुला है

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील पर संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए, निश्चित रूप से, इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्त किए जाने के निर्णय से मजबूत होती है, जिसे उन गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था जिनके साक्ष्य उसकी उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य की प्रशंसा करने की उतनी ही व्यापक शक्तियां हैं जितनी कि दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में हैं, बशर्ते कि अभियुक्त व्यक्ति की निर्दोषता का अनुमान, जिसके साथ अभियुक्त व्यक्ति विचारण न्यायालय में शुरू होता है, अपीलीय स्तर तक भी जारी रहता है और यह कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने दोषमुक्ति का आदेश दर्ज किया था।

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात्, सूरजपाल सिंह बनाम राज्य ए आईआर 1952 एस सी 52; विलायत खान बनाम यू.पी. राज्य। ए. आई. आर 1953 एस. सी. 122) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं था। के. गोपाल रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ ए.पी (1979) 1 एस. सी. सी. 355, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां विचारण न्यायालय अपने आप को काल्पनिक संदेहों से ग्रस्त होने की अनुमति देता है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करता है और साक्ष्य का दृष्टिकोण लेता है जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन का उपहास किया जाए।

[जोर दिया गया]

करण आनंद बनाम कमल बख्शी 7 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

5. परिस्थितियों में, बरी होने का निष्कर्ष दर्ज किया गया

⁷ 2015 (4) आर.सी.आर. (सीआरएल.) 595

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख की सामग्री के प्रतिकूल या विपरीत नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में अभियुक्त/प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क में कोई दुर्बलता नहीं है। यह एक स्थापित कानून है जैसा कि सी. एंटनी बनाम. के.जी में आयोजित किया गया है। राघवन नायर, 2002 (4) आर. सी. आर. (दांडिक) 750 ने कहा कि भले ही साक्ष्य के मूल्यांकन पर दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, न्यायालय अभियुक्त को बरी करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बरी किए जाने के मामलों में, उसके पक्ष में दोहरी धारणा है; पहला निर्दोष होने का अनुमान, और दूसरा अभियुक्त के बरी किए जाने के बाद, न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह निर्णायक रूप से नहीं दिखाया जाता है कि अपराध का निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है।

[जोर दिया गया]

रेखा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ⁸ में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

13. आवेदन की गई अनुमति देते समय, इस न्यायालय को यह ध्यान रखना है कि बरी होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के तहत उसके लिए निर्दोष होने का अनुमान उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा फिर से लागू, पुष्टि और मजबूत की जाती है। जब अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हों, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

[जोर दिया गया]

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णय इस आशय के हैं कि जहां एक अपीलीय न्यायालय को उन साक्ष्यों की समीक्षा करने, पुनः मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित किया गया है, यह समान रूप से सत्य है कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है, पहला अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषता के अनुमान के कारण और दूसरा इस तथ्य के कारण कि सक्षम न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है और इसलिए, यदि दो उचित निष्कर्ष संभव थे।

⁸ 2019 (4) आर.सी.आर. (सीआरएल.) 294

वीरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को केवल इसलिए बाधित नहीं करना चाहिए क्योंकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की तुलना में किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच सकता था। तथापि, जहां इसके विरुद्ध अपील किया गया निर्णय पूरी तरह से विकृत है और निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या अपवर्जन करके या अप्रासंगिक या अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं, तो अपीलीय न्यायालय उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें अलग करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा।

(17) इसके ऊपर की विस्तृत चर्चा और माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर एक उचित दृष्टिकोण है, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(18) इसलिए, यह न्यायालय विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखता है और इसलिए अपील करने की अनुमति देने का आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

रिपोर्टर-दिव्या गुरने

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।



Advocate Megha Tak